भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1103
उत्तर देने की तारीखः 28.07.2021

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा

1103. श्री सतीश चंद्र दुबेः
श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदीः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास लाभार्थियों के अनुसार सामाजिक क्षेत्र की सभी योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं,तो इसके क्या कारण है;और
(घ) सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के सुचारु संचालन पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (घ): जी हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में सूचना-निगरानी,मूल्यांकन एवं सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए) नामक एक स्कीम बनाई है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से विभाग की सभी स्कीमों की सामाजिक लेखा-परीक्षाएं की जानी हैं। ये सामाजिक लेखा परीक्षाएं राज्य की सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों (एसएयू) और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के माध्यम से की जाती हैं।

******